राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा के द्वारा भारतीय ज्ञान परंपरा की खोज

डॉ. लक्की शर्मा,
एसोसिएट प्रोफेसर,
आर आर बावा डी.ए.वी. कॉलेज फॉर गर्ल्स, बटाला।

शोध सारांश (Abstract)

भारतीय शिक्षा व्यवस्था एक लंबे समय से औपनिवेशिक प्रभाव के अधीन रही है, जहाँ अंग्रेजी भाषा और पद्धतियों ने भारतीय भाषाओं और ज्ञान परंपरा को हाशिए पर डाल दिया। हालाँकि, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस स्थिति में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का प्रयास करती है। इस नीति में मातृभाषा को प्राथमिक शिक्षा का माध्यम बनाने के साथ-साथ भारतीय ज्ञान परंपरा को पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बनाया गया है। यह शोधपत्र वैश्विक शिक्षा प्रणालियों की तुलना के माध्यम से भारत की शिक्षा नीति, उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, वर्तमान प्रयासों, चुनौतियों और संभावित समाधानों का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

मुख्य शब्द (keywords)
राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपरा, औपनिवेशिक प्रभाव, गुरुकुल योग, आयुर्वेद, संस्कृत, भाषा नीति, नवाचार।

CGCTA

भारतीय शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
प्राचीन भारत में शिक्षा का आधार भारतीय भाषाएँ रही हैं। संस्कृत, पालि, प्राकृत, तमिल आदि। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों में दर्शन, खगोलशास्त्र, चिकित्सा, गणित, राजनीति आदि विषयों की उच्च शिक्षा मातृभाषाओं में होती थी। शिक्षा का यह स्वरूप अनुभव, संवाद, और नैतिक मूल्यों पर आधारित था।

चीन की शिक्षा प्रणाली और मंदारिन की भूमिका
चीन में मंदारिन को शिक्षा, प्रशासन और अनुसंधान का मूल माध्यम बनाया गया है। यहाँ तक कि इंजीनियरिंग, चिकित्सा और विज्ञान जैसे विषय भी मंदारिन में पढ़ाए जाते हैं। 1990 के दशक में चीन ने 'मूल भाषा में विज्ञान' का अभियान चलाया, जिससे शोध की गुणवत्ता और गहराई बढ़ी। UNESCO की रिपोर्ट के अनुसार, मातृभाषा में शिक्षा से बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता में 40 प्रतिशत तक सुधार होता है।

फ्रांस में फ्रेंच भाषा की शिक्षा में स्वीकार्यता
फ्रांस की शिक्षा प्रणाली फ्रेंच भाषा पर आधारित है। फ्रांसीसी अकादमियां भाषा की शुद्धता बनाए रखने के लिए सक्रिय हैं। यहाँ तक कि विदेशी छात्रों को भी फ्रेंच सीखनी पड़ती है। इस भाषा-आधारित आत्मगौरव ने फ्रांस को वैश्विक मंच पर सांस्कृतिक रूप से सशक्त बनाया है।
भारत में औपनिवेशिक शासन और अंग्रेजी की वर्चस्वता

ब्रिटिश शासन ने भारत की पारंपरिक शिक्षा प्रणाली को सुनियोजित ढंग से नष्ट किया। अंग्रेजी भाषा को "सभ्यता" और "प्रगति" का प्रतीक बनाकर भारतीयों को अपने ही ज्ञान से विमुख कर दिया गया। परिणामस्वरूप, भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक लेखन और अनुसंधान लगभग ठप हो गया।

लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा नीतिः एक मानसिक क्रांति
1835 में मैकॉले ने ब्रिटिश संसद में कहा थाः "We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern-"
उनकी यह नीति भारतीयों को मानसिक रूप से अंग्रेज बनाने का प्रयास थी। इसके परिणामस्वरूप गुरुकुल व्यवस्था की उपेक्षा शुरू हुई।

गुरुकुल परंपरा का विनाश
1830 के दशक तक भारत में लाखों गुरुकुल थे, जिनमें निरूशुल्क शिक्षा, भोजन और निवास मिलता था। विलियम एडम की रिपोर्ट के अनुसार, बंगाल, बिहार और मद्रास प्रांतों में शिक्षा का स्तर बहुत उच्च था। लेकिन ब्रिटिश नीतियों ने इन संस्थानों को "अनउपयोगी" घोषित कर दिया, जिसने ज्ञान परंपरा को बहुत क्षति पहुंचाई। भारतीयों का आत्मविश्वास डोल गया और उन्हें अंग्रेजी पढ़ने पर मजबूर किया गया उनकी आर्थिक व्यवस्था भी बर्बाद कर दी गई और वह अंग्रेजों के तलवे चाटने पर मजबूर हो गए । लघु व्यवसाय बर्बाद कर दिए गए। किसान मजदूर हो गए और केवल वही लोग गुजर-बसर कर सके जो अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के अनुसार जीवन जीने लगे और अंग्रेजों के पिट्ठू बन गए । मरता क्या ना करता। अंग्रेजों के लंबे राज्यकाल में बहुत सारे भारतीयों ने धीरे-धीरे इस व्यवस्था को स्वीकार कर लिया और अपनी ज्ञान परंपरा से नाता तोड़ लिया। इस तरह औपनिवेशिक काल में नौकरियों का माध्यम अंग्रेजी होने की वजह से अंग्रेजी शिक्षा एक वर्ग विशेष की पहचान बन गई। परिणामस्वरूप, भारतीय भाषाओं को "गँवारू" समझा जाने लगा और भारतीय ज्ञान परंपरा को "अप्रासंगिक" मान लिया गया।

भारतीय स्वतंत्रता के बाद की शिक्षा नीतियां
भारतीय स्वतंत्रता के बाद शिक्षा नीति के कई दौर आए जिसमें मातृभाषा और भारतीय ज्ञान परंपरा को स्थान देने का प्रयास हुआ। परंतु यह सिद्धांत अधिक था और व्यावहारिक कम। जैसे राधा कृष्ण आयोग 1948- 1949 उच्च शिक्षा के लिए गठित इस आयोग ने भारतीय संस्कृति और दर्शन को शिक्षा में शामिल करने के सिफारिश तो की परंतु यह केवल विश्वविद्यालय स्तर तक थी। परंतु व्यावहारिक रूप पर किसी लागू करने के लिए कुछ भी नहीं किया। कोठारी आयोग 1964-66 में इस आयोग ने भारतीयकरण पर बल देते हुए सुझाव दिया कि शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए क्योंकि इसके साथ राष्ट्रीय एकता व संस्कृति सुदृढ़ होती है परंतु यह केवल एक सुझाव ही रहा। 1968 में फिर से एक शिक्षा नीति आई जिसमें तीन भाषाओं वाले सूत्र की बात की गयी और मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा देने का सुझाव दिया गया परंतु यह भी लागू नहीं हो सका। फिर 1986 में एक और शिक्षा नीति आई जिसको 1992 में दोबारा संशोधित किया गया। इस नीति ने क्षेत्रीय भाषाओं और भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहन देने की बात की लेकिन निजीकरण और अंग्रेजी माध्यम के बढ़ते चरणबद्ध विकास के कारण मातृभाषा को उपयुक्त स्थान नहीं मिल पाया। वैश्वीकरण के दौर में भी जैसे मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में आती गई विदेशी संस्कार और

विदेशी भाषा की जुड़े भारत में और भी मजबूत होती गई और भारतीय विज्ञान परंपरा को जैसे नई पीढ़ी ने भुला सा दिया इस परंपरा से जुड़े हुए लोग हास्य पर चले गए और धीरे-धीरे समझ में मजाक का कारण बनने लगे उनके लिए रोजगार के अवसर लगभग खत्म हो गए क्षेत्रीय भाषाओं व राष्ट्रीय भाषा हिंदी को बोलने वाले लोगों को हेय दृष्टि से देखा जाने लगा आज भी उन्हें उच्च पद पर बैठने का मौका तक नहीं दिया जाता है और उनकी योग्यता को कम आंका जाता है ।

एनसीईआरटी यूजीसी और सीबीएसई जैसी कई संस्थाओं ने समय-समय पर भारतीय ज्ञान परंपरा को पाठ्यक्रम मे लाने का प्रयास किया परंतु यह सारे प्रयास संगठित नही थे और इनमें इच्छा शक्ति का भी अभाव था। आंशिक होने की वजह से ज्यादातर प्रयास असफल ही रहे। उच्च पदों पर बैठे लोग भी अधिकतर अंग्रेजी भाषी थे और उसी को प्रोत्साहित करते थे। इसलिए यह कोशिशें भी समस्या को ठीक नहीं कर पाई। हैरानी की बात है कि भारत की बहुसंख्यक जनसंख्या या तो हिंदी भाषी है या क्षेत्रीय भाषी। फिर भी इन्हें समाज में दरकिनार कर दिया गया है और कुछ अंग्रेजी भाषा लोगों का दबदबा स्थापित कर दिया गया है। आज भी बहुत से लोग भारतीय परंपरा को इंडियन नॉलेज सिस्टम के रूप में ठीक वैसे ही देखते हैं जैसे धर्म को रिलिजन और विवाह को मैरिज में अनुवादित करना। जबकि दोनों में जमीन आसमान का अंतर है भारत में विवाह दो परिवारों का मिलन है जबकि मैरिज दो व्यक्तियों का इसी तरह से भारत में धर्म है धर्मः इति धारयति अर्थात धर्म वह है जिसे धारण किया जाता है व्यवहार में लाया जाता है नैतिकता पर आधारित होता है चरित्रवान बनता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति देता है। जबकि रिलिजन में अलग-अलग मत-मतांतर अंतर भी आ जाते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा को जानने के लिए भारतीय भाषाओं सभ्यता संस्कृति और उसके इतिहास का ज्ञान होना परम आवश्यक है और इसी जरूरत को नई राष्ट्रीय नीति पूरा करने का सार्थक प्रयास करती नजर आ रही है। अंग्रेजी और श्वेतपोश नौकरी की लालसा स्थितियों को और भी बिगाड़ दिया। हम देखते हैं कि पूर्ववर्ती शिक्षा नीतियों में मातृभाषा की पूर्णता उपेक्षा की गई है। 1968 की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने मातृभाषा में शिक्षा की सिफारिश की, लेकिन उसे सही ढंग से लागू नहीं किया गया। 1986 की इस शिक्षा नीति में भी स्थानीय भाषाओं का जिक्र तो था, पर अंग्रेजी भाषा का दबदबा बना रहा।

नई शिक्षा नीति (NEP 2020) और त्रिभाषा नीति
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पहली ऐसी नीति है जिसने "भाषा को केवल माध्यम नहीं, बल्कि विचार की भाषा" माना है। इसमें कहा गया है कि कक्षा 5 से 8 मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा या स्थानीय भाषा में दी जाए। इसका उद्देश्य बच्चों को उनकी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ना है और भारतीय ज्ञान परंपरा की पुनः खोज के लिए उन्हें प्रेरित करना है तांकि वह अपनी जड़ों से पोषित व पलवित भारतीय शिक्षा नीति के अनुसार कार्य करते हुए भारत को विश्व गुरु का पद दिला सके। मातृभाषा की भूमिका और संज्ञानात्मक लाभ के बारे में भी विद्वानों ने बहुत चर्चा की है और शोध कार्य किया है। उनके शोध से सिद्ध हुआ है कि मातृभाषा में सीखने वाले छात्र बेहतर तर्कशक्ति, स्मृति और रचनात्मकता का प्रदर्शन करते हैं। एक UNESCO रिपोर्ट कहती है: "Children learn best in their mother tongue in the early years-"

भारतीय ज्ञान परंपरा एक व्यापक प्रणाली है जिसमेंः योग, आयुर्वेद, धातु विज्ञान, गणित (शून्य, बीजगणित), खगोल, संगीत, कला, और दर्शन जैसे विषय शामिल हैं। इनका मूल स्रोत वेद,

उपनिषद, पुराण, तंत्र, नाट्यशास्त्र, और लौकिक ग्रंथ हैं। विदेशी संस्थानों में प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान पर कार्य किया जा रहा है और यह कार्य गहन दृष्टि पर आधारित है। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि MIT में योग और ध्यान पर रिसर्च, Harvard Divinity School में वेदांत पर पाठ्यक्रम Oxford में संस्कृत पांडुलिपियों पर प्रोजेक्ट Google और IBM द्वारा ध्यान तकनीकों पर AI आधारित रिसर्च जब विश्व भारतीय ज्ञान विज्ञान से लाभ ले रहा है, तब भारत को स्वयं इसका दोहन करना होगा। भारतीय औषधियों पर विदेशी पेटेंट नीमः नीम के कीटनाशक गुणों पर 1994 में अमेरिकी कंपनी ने पेटेंट ले लिया हल्दीः अमेरिका में घाव भरने की प्रक्रिया पर पेटेंट लिया गया। भारतीय वैज्ञानिकों ने इन पेटेंट को रद्द करवाया। लेकिन यह इस बात का संकेत है कि हमारे ज्ञान को जब तक दस्तावेजी रुप नहीं किया जाएगा, वह विदेशी नियंत्रण में जाता रहेगा

कुंभ 2025 के समय में भारतीय ज्ञान मे जागी वैश्विक रुचि
प्रयागराज कुंभ 2025 में भारी संख्या में विदेशी यात्रियों तथा विदेशी मीडिया ने भारत की यात्रा की और भारतीय ज्ञान को खंगाला। अनेक विश्व के प्रतिष्ठित लोगों ने भारतीय अखाड़े में दीक्षा ग्रहण की और भारतीय परंपराओं को अंगीकार किया आज पूरे विश्व में योग, आयुर्वेद, खगोल विज्ञान पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियाँ प्रस्तावित हैं। जो को तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल गई है आज भी जापान, अमेरिका, रूस और जर्मनी से विद्वान भारतीय परंपराओं को समझने और अनुसंधान के लिए आ रहे हैं। किस संदर्भ में हम जर्मनी का उदाहरण ले सकते हैं जहां भारतीय भाषा संस्कृत का अध्ययन करवाया जाता है और पतंजलि के अष्टाध्याय का ज्ञान विद्यार्थियों को दिया जाता है और यह माना जाता है की भाषा विज्ञान को अष्टाध्याय के बिना समझा नहीं जा सकता।

भारत की प्राचीन पतंजलि योग परंपरा जो आत्मसंयम ध्यान और शरीर - मन के संतुलन पर आधारित है, वह अब वैश्विक स्तर पर सम्मानित है। भारतीय ज्ञान परंपरा तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसे औपचारिक रूप में भारतीय विद्यार्थियों की शिक्षा का भाग बन चुकी है तांकि उनका मानसिक, शारीरिक और नैतिक विकास किया जा सके। भारत सरकार ने योग को एक स्वास्थ्य, सांस्कृतिक और वैश्विक आंदोलन के रूप में विकसित करने के लिए बहुआयामी प्रयास किए हैं। इन प्रयासों से न केवल भारतीय नागरिकों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान को भी सुदृढ़ता मिली है। भविष्य में भी योग को और अधिक वैज्ञानिक एवं वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाने की दिशा में सरकारी प्रयास जारी रहेंगे। भारत में योग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा अनेक स्तरों पर प्रयास किए गए हैं। ये प्रयास न केवल योग को राष्ट्रीय पहचान देने के लिए हैं, बल्कि उसे वैश्विक मंच पर भी स्थापित करने की दिशा में किए गए हैं।

नीचे कुछ प्रमुख सरकारी प्रयासों का विवरण दिया गया है:

1. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की स्थापना (International Day of Yoga)
वर्ष 2014 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में 21 जून को 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस' घोषित करने का प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव 177 देशों द्वारा सहमत हुआ और 21 जून 2015 को पहला योग दिवस पूरे विश्व में मनाया गया। इसके माध्यम से भारत ने योग को विश्व स्तर पर एक सांस्कृतिक विरासत के रूप में स्थापित किया।

2. आयुष मंत्रालय (Ministry of AYUSH) की स्थापना
2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देना है। मंत्रालय योग से संबंधित नीतियाँ बनाता है, शोध कार्यों को बढ़ावा देता है और योग को स्वास्थ्य प्रणाली में सम्मिलित करने के लिए कार्य करता है।

3. योग को शिक्षा प्रणाली में सम्मिलित करना
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 में योग को एक अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया है। प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक छात्रों को योग और ध्यान का अभ्यास करवाने पर बल दिया गया है। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी योग शामिल किया गया है।

4. मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (MDNIY)
यह संस्थान नई दिल्ली में स्थित है और भारत सरकार द्वारा संचालित है। यहां योग में डिप्लोमा, स्नातक और परास्नातक स्तर की शिक्षा दी जाती है। यह संस्थान योग शिक्षकों को प्रशिक्षित करता है और वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देता है।

5. CCRYN (Central Council for Research in Yoga & Naturopathy)
यह आयुष मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है जो योग और प्राकृतिक चिकित्सा में अनुसंधान को प्रोत्साहित करता है। यह संगठन योग से संबंधित पब्लिकेशन, कार्यशालाओं और सम्मेलनों का आयोजन करता है।

CGCTA

6. FIT India Movement और योग
2019 में शुरू किया गया "Fit India Movement" स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाते हैं।

7. अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव और योग केंद्रों की स्थापना
ऋषिकेश और अन्य प्रमुख शहरों में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन होता है, जिसमें देश-विदेश के योग प्रेमी भाग लेते हैं। सरकार द्वारा देशभर में योग प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की जा रही है, विशेषकर ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में।

8. डिजिटल प्लेटफॉर्म पर योग
सरकार ने mYoga App लॉन्च किया है जिसमें WHO (World Health Organization) के सहयोग से योग अभ्यास की जानकारी कई भाषाओं में दी गई है। यह पहल डिजिटल भारत और आत्मनिर्भर भारत मिशन के अंतर्गत योग को विश्वभर में पहुंचाने की दिशा में अहम कदम है।

9. आयुष्मान भारत और योग
आयुष्मान भारत योजना के तहत "Health and Wellness Centres" में योग सत्र आयोजित किए जाते हैं। इससे योग को ग्रामीण और वंचित समुदायों तक पहुंचाने का प्रयास हो रहा है।

10. रोजगार सृजन और योग
सरकार योग प्रशिक्षकों और चिकित्सकों के लिए सरकारी एवं निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित कर रही है। योग को पर्यटन (Wellness Tourism) से जोड़ने की नीति भी अपनाई जा रही है।

भारत सरकार की तरफ से आयुर्वेद को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए कार्यः
भारत सरकार ने आयुर्वेद को प्रोत्साहित करने के लिए कई महत्वपूर्ण और ठोस कदम उठाए हैं। ये प्रयास आयुर्वेद को एक आधुनिक, वैज्ञानिक और वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली के रूप में स्थापित करने की दिशा में किए गए हैं।

101. 1. आयुष मंत्रालय (Ministry of AYUSH) की स्थापना-2014
भारत सरकार ने वर्ष 2014 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से अलग एक स्वतंत्र आयुष मंत्रालय स्थापित किया। इसका उद्देश्य आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, सोवा-रिग्पा और होम्योपैथी जैसी भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देना है। मंत्रालय नीति निर्माण, शिक्षा, अनुसंधान और सार्वजनिक स्वास्थ्य में आयुर्वेद के एकीकरण के लिए काम करता है।

2. आयुर्वेदिक संस्थानों की स्थापना और उन्नयन
सरकार ने देशभर में AIIMS जैसे मॉडल आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने की योजना बनाई है। All India Institute of Ayurveda (AIIA) नई दिल्ली-यह आयुर्वेद में उच्चस्तरीय शिक्षा, शोध और इलाज का प्रमुख केंद्र है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (NIA) जयपुर को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है। गुजरात के जामनगर में आयुर्वेद विश्वविद्यालय को भी उन्नत किया गया है।

3. शिक्षा और पाठ्यक्रम में सुधार
आयुर्वेदिक शिक्षा को आधुनिक चिकित्सा पद्धति के साथ समन्वय किया गया है NCISM (National Commission for Indian System of Medicine) की स्थापना की गई है जो आयुर्वेदिक कॉलेजों की गुणवत्ता और मान्यता सुनिश्चित करती है। BAMS (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी) को मुख्यधारा में लाया गया है।

4. रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा
CCRAS (Central Council for Research in Ayurvedic Sciences) के माध्यम से वैज्ञानिक शोध, औषधीय परीक्षण और नए उपचार विकसित किए जा रहे हैं। COVID-19 के दौरान आयुर्वेद आधारित प्रतिरक्षा-वर्धक काढ़े, औषधियाँ और आयुष-64 जैसी दवाएं प्रचारित की गईं। WHO के सहयोग से Global Centre for Traditional Medicine (GC&TM) की स्थापना जामनगर, गुजरात में की गई।

5. आयुर्वेद और डिजिटल इंडिया
सरकार ने आयुर्वेद को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए कई ऐप्स और पोर्टल लॉन्च किए हैंः e-AUSHADHI पोर्टल औषधियों की जानकारी और प्रबंधन के लिए। AYUSH Sanjivani App -

आयुर्वेदिक उपायों के प्रभाव का सर्वेक्षण । National AYUSH Morbidity and Standardized Terminologies (NAMSTP)

6. आयुर्वेद के प्रचार-प्रसार के लिए महोत्सव और सम्मेलन
हर वर्ष राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस (Dhanvantari Jayanti के दिन) मनाया जाता है। आयुष एक्सपो, आयुर्वेद महोत्सव, और वेलनेस फेस्टिवल्स में भारत और अन्य देशों की भागीदारी होती है।

7. सार्वजनिक स्वास्थ्य योजनाओं में आयुर्वेद का समावेश
आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत "Health and Wellness Centres" में आयुर्वेद आधारित उपचार और जीवनशैली परामर्श दिए जाते हैं। ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में आयुर्वेद औषधालय स्थापित किए गए हैं।

8. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार
भारत सरकार ने कई देशों के साथ MoU (Memorandum of Understanding) पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिले। WHO द्वारा मान्यता प्राप्त आयुर्वेदिक गाइडलाइंस और शोध कार्य बढ़े हैं। AYUSH Export Promotion Council (AYUSHEPC) की स्थापना से आयुर्वेदिक औषधियों के निर्यात को प्रोत्साहन मिला हैं।

9. रोजगार और स्टार्टअप में बढ़ावा
सरकार ने आयुर्वेद आधारित स्टार्टअप्स, औषधि कंपनियों, और वेलनेस उद्योगों को वित्तीय सहायता और मार्गदर्शन दिया है। AYUSH Entrepreneurship Development Programmes के तहत नए उद्यमियों को ट्रेनिंग दी जाती है।

10. वनस्पति संरक्षण और औषधीय खेती
आयुर्वेदिक औषधियों के लिए आवश्यक जड़ी-बूटियों की खेती को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (NMPB) द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं। किसानों को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य आयुर्वेद को केवल भारत तक सीमित न रखकर वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली के रूप में विकसित करना है। आधुनिक विज्ञान, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, अनुसंधान और वैश्विक भागीदारी के माध्यम से आयुर्वेद को पुनर्जीवित किया जा रहा है। यह भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा को सशक्त करने का एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-निर्माण द्वारा भारतीय ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा
भारतीय ज्ञान विज्ञान के अध्ययन केंद्रों की स्थापनाः IITs और IIMs में ऐसे कई केंद्र खोले जा सकते हैं।
संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्यक्रमः जैसे केरल के स्कूलों में आयुर्वेद का परिचय।
प्राचीन विज्ञान का समावेशः आचार्य चाणक्य, नागार्जुन, भास्कराचार्य के योगदान पर अध्ययन।
चुनौतियाँ
• मानसिकता की समस्याः अंग्रेजी को ही "सफलता की गारंटी" मानना ।
• संसाधनः मातृभाषाओं में उच्च गुणवत्ता की पुस्तकें और शिक्षण सामग्री का अभाव ।

CGCTA

• शिक्षकों की कमीः प्रशिक्षित शिक्षक नहीं हैं जो मातृभाषा में आधुनिक विषय पढ़ा सकें ।
• बाजार की भाषाः नौकरियाँ अभी भी अंग्रेजी केंद्रित हैं ।

समाधान
• टेक्नोलॉजी का प्रयोग: AI और डिजिटल प्लेटफॉर्म से मातृभाषा में E-content
• शिक्षक प्रशिक्षणः मातृभाषा में विज्ञान, गणित पढ़ाने के लिए विशेष प्रशिक्षण।
• जन-जागरूकता अभियानः मातृभाषा और भारतीय ज्ञान परंपरा को सम्मान देने के लिए अभियान चलाना
• उद्यमिता और रोजगारः स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना (जैसे आयुर्वेदिक उत्पाद)

निष्कर्ष
मातृभाषा न केवल भावों की अभिव्यक्ति का साधन है, बल्कि वह हमारी सोच की धुरी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस धुरी को केंद्र में लाकर शिक्षा के भारतीयकरण, लोकल से ग्लोबल की ओर बढ़ने की दिशा में सार्थक कदम है। अब जरूरत है कि इस नीति का जमीनी कार्यान्वयन हो, जिससे हमारी आने वाली पीठियाँ अपनी जड़ों से जुड़कर वैश्विक मंच पर नेतृत्व कर सकें।

संदर्भ ग्रंथ-सूची

1. प्राचीन भारतीय शिक्षा परंपरा और मातृभाषा की भूमिकाः "प्राचीन भारत में शिक्षा का आधार भारतीय भाषाएं रहीं हैं... शिक्षा का यह स्वरूप अनुभव, संवाद और नैतिक मूल्यों पर आधारित था।" (Mukherjee, "Education in Ancient India", National Book Trust, 2010, P-23)

2. चीन और फ्रांस की मातृभाषा-आधारित शिक्षा प्रणालीः "1990 के दशक में चीन ने 'मूल भाषा में विज्ञान' कार्यक्रम चलाया...." (Zhou Minglang, "Language Policy in the People's Republic of China, "Springer, 2004, p-145) "फ्रांस की शिक्षा नीति फ्रेंच भाषा पर आधारित है..."(Fishman, Joshua A-, "Handbook of Language and Ethnic Identity" Oxford UP, 1999, p-109)

3. ब्रिटिश औपनिवेशिक शिक्षा नीति का प्रभावः "1835 में मैकॉले ने ब्रिटिश संसद में कहा- "We must at present do our best to form a class---"(Macaulay, Thomas B-, "Minute on Indian Education", 1835, cited in Nurullah and Naik, 2001, p-118)

4. स्वतंत्रता के बाद की शिक्षा नीतियाँ: "1948-49 की राधाकृष्णन आयोग रिपोर्ट ने भारतीय संस्कृति को शिक्षा में शामिल करने की सिफारिश की..." (Report of the University Education Commission, 1948-49) "1964-66 कोठारी आयोग ने मातृभाषा में शिक्षा का सुझाव दिया... "(Kothari Commission Report, Govt- of India, 1966, p-37)

5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और मातृभाषाः "NEP 2020 ने कहा है कि कक्षा 5 से 8 तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा में पढ़ाई हो..." (NEP 2020, Ministry of Education, Government of

CGCTA

India, p14) "UNESCO की रिपोर्ट कहती है: "Children learn best in their mother tongue in the early years" (UNESCO, "If You Don't Understand, How Can You Learn?", 2016, p- 9)

6. भारतीय ज्ञान परंपरा का वैश्विक प्रसारः "MIT में योग और ध्यान पर रिसर्च, Harvard Divinity School में वेद अध्ययन... "Caplan, Mariana "Eyes Wide Open: Cultivating Discernment on the Spiritual Path," Sounds True, 2009, p- 221)"Google और IBM जैसी कंपनियाँ ध्यान आधारित AI विकसित कर रही हैं.... "(Singer, Tania and Matthieu Ricard, "The Neurobiology of Meditation, "in Mind andLife, 2012)

7. सरकार द्वारा किए गए प्रयास (AYUSH और योग): "2014 में AYUSH मंत्रालय की स्थापना हुई.."(Ministry of AYUSH, Govt.of India, Annual Report 2015-16) "21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा.. "(United Nations Resolution A/RES/69/131, 2014)"mYoga App और Digital Platform का शुभारंभ.. " (WHO & Ministry of AYUSH,"mYoga App Overview", 2021)

CGCTA